भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 950
दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की गिरती स्थिति

950. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक(जीएचआई) 2022 में भारत की स्थिति और अधिक गिर 121 देशों में से 107वें स्थान पर आ गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति को सुधारने में सरकार क्यों विफल रही है;
(घ) ऐसी विकट स्थिति को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
(ड.) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ङ): वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) भारत की सही तस्वीर नहीं दर्शाता क्योंकि यह ''भुखमरी'' का एक त्रुटिपूर्ण पैमाना है। इसे अंकित मान के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह न तो उपयुक्त है और न ही किसी देश में व्याप्त भूख का प्रतिनिधित्व करता है। इसके चार सूचकों में से केवल एक सूचक यानी अल्पपोषण भूख से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है। ठिगनापन और दुबलापन दोनों सूचक विभिन्न अन्य कारकों जैसे स्वच्छता, आनुवांशिकी, पर्यावरण और भूख के अलावा भोजन आहार के उपयोग के जटिल सम्मिश्रण के परिणाम हैं, जिन्हें जीएचआई में ठिगनेपन और दुबलेपन का प्रेरक/ परिणामी कारक माना जाता है। इसके साथ ही इस बात के कम ही प्रमाण हैं कि चौथा सूचक यानी बाल मृत्यु दर भूख का परिणाम है।

कंसर्न वर्ल्डवाइड और वैल्थहंगरहिल्फे द्वारा जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार, भारत 29.1 के स्कोर के साथ 121 देशों में 107वें स्थान पर था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 27.5 के स्कोर के साथ 116 देशों में 101वें स्थान पर रहा था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के तहत देश में समय-समय पर पोषण सूचकों पर डेटा एकत्र किया जाता है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण सूचकों में एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5%, दुबलापन 21.0% से घटकर 19.3% और कम वजन का प्रचलन 35.8% से घटकर 32.1% रह गया है।

सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और इस मुद्दे के समाधान के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रयासों का कायाकल्प किया गया है और उन्हें 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) के रूप में अभिसरित किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का

पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के माध्यम से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है।

पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष के माध्यम से कल्याण पर केंद्रित है। यह अभिसरण, शासन और क्षमता निर्माण के स्तंभों पर टिका है। पोषण अभियान पहुंच के लिए प्रमुख स्तंभ है और इसमें पोषण सहयोग, आईसीटी हस्तक्षेप, मीडिया पैरवी और अनुसंधान, सामुदायिक पहुंच और जन आंदोलन से संबंधित नवाचार शामिल हैं। पोषण की गुणवत्ता और मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण में सुधार, सेवाओं के त्वरित पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए पूरक पोषण के प्रावधान की रीयल टाइम निगरानी के संबंध में शासन में सुधार के लिए एक सशक्त आईसीटी सक्षम मंच, 'पोषण ट्रैकर' के तहत वितरण को सुदृढ़ बनाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पोषण सहयोग कार्यक्रम और सेवा प्रदायगी में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के लिए सरकार ने दिनांक 13.01.2021 को सुव्यवस्थित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में पूरक पोषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ड्यूटीधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करने, आईटी सक्षम डेटा प्रबंधन और निगरानी, आयुष के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने, पोषण संबंधी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए खरीद और अभिसरण पर जोर दिया गया है।

*****